

बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, 2021 पर

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल के लिए स्थायी समिति के समक्ष नागरिक समाज की अभिव्यक्ति

7 नवंबर, 2024

यह प्रस्तुतीकरण भारत में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लागू करने और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले लगभग 200 संगठनों और व्यक्तियों की ओर से है। हम दो नेटवर्क हैं - **किशोरों की चिंताओं की वकालत करने के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीएएसी),¹** और **यंग वॉयस वर्किंग ग्रुप (वाईवीडब्ल्यूजी)²** संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस प्रतिनिधित्व को देश भर के 75 व्यक्तियों और संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। अभिव्यक्ति के अंत में सदस्यों/समर्थकों की विस्तृत सूची शामिल है।

हमारी चिंताएँ बाल और जल्द विवाह की समस्या से निपटने के लिए कड़े विधायी समाधानों पर अनुचित निर्भरता से संबंधित हैं, जिसके परिणाम उन महिलाओं और लड़कियों के लिए हानिकारक हैं जिनके लाभ के लिए कानून बनाया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) में लगातार संशोधन इस प्रवृत्ति के संकेत हैं। 2017 में, कर्नाटक में पीसीएमए ((बाल विवाह निषेध अधिनियम) में संशोधन किया गया, जिससे बाल विवाह की स्थिति को नाबालिग पक्ष के विकल्प पर 'वैध यद्यपि शून्यकरणीय' से बदलकर 'प्रारंभ से शून्य' (कोई कानूनी प्रभाव नहीं) कर दिया गया; 2020 में, हरियाणा ने इसी तरह का संशोधन लागू किया। इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, जब महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक, 2021 संसद में पेश किया गया, तो इसे इस संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। तब से यह विधेयक समाप्त हो चुका है; और अब, 2024 में, हिमाचल प्रदेश द्वारा

¹ **एनसीएएसी** (नैशनल कोअलिशन फॉर ऐडवोकेटिंग ऐडोलेसेंट कंसर्नस) सात राज्यों में महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी अधिकारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यौन और लिंग आधारित हिंसा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल, शिक्षा और पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों का गठबंधन। (दिल्ली - पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, निरंतर ट्रस्ट, एक्शन इंडिया, बटरफ्लाईज़, काउंसल टू सिव्योर जस्टिस, हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, समा रिसोर्स सेंटर फॉर वुमन एंड हेल्थ, शक्ति शालीनी, निकोल रेंजेल; राजस्थान - महिला जन अधिकार समिति, विशाखा; उत्तर प्रदेश - द वाईपी फाउंडेशन; पश्चिम बंगाल - डिसेबिलिटी राइट्स सेंटर, प्राजक; गुजरात - एरिया नेटवर्किंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, साहियार स्त्री संगठन; मुंबई - महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडल, प्रेरणा, सेंटर फॉर इनक्रायरी इन हेल्थ एंड एलाइड थीम्स, राति फाउंडेशन, महारुख एडनवाला; कर्नाटका - एंफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव)

² **वाईवीडब्ल्यूजी** (यंग वॉयस वर्किंग ग्रुप) 17 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) से 95 नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों का एक सहयोग है, जो युवा लोगों के अधिकारों, विशेष रूप से उनकी बात सुने जाने के अधिकार को बनाए रखने के लिए समर्पित है। वाईवीडब्ल्यूजी ने युवा आवाज़ राष्ट्रीय आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें 2,500 से अधिक हाशिए पर रहने वाले बच्चे, किशोर और युवा शामिल हुए, जिन्होंने महिलाओं के कानूनी विवाह की आयु को 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का विरोध किया - और बाल/अल्प आयु में विवाह के मामलों को व्यापक और स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए सिफारिशें प्रदान कीं।

महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के लिए पीसीएमए में संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है।

कर्नाटक और हरियाणा में कम उम्र में विवाह को 'प्रारंभ से शून्य' और अमान्य घोषित करने वाले संशोधन लागू हो गए हैं, लेकिन विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का विवादित मुद्दा अभी भी लंबित है, और इसलिए इसे समझने की आवश्यकता है।

बाल विवाह (संशोधन) बिल, 2021 (जिसे 'बिल' के रूप में संदर्भित किया गया है) का उद्देश्य "मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, पोषण स्तरों में सुधार, जन्म के समय लिंग अनुपात को संतुलित करना, ... महिलाओं का सशक्तिकरण, लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिला श्रमिक बल में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना" है, जिसके लिए महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ये व्यापक लक्ष्य भारत सरकार की दिनांक 4.6.2020 की अधिसूचना के अनुरूप हैं, जिसमें "मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने की आवश्यकता, पोषण स्तरों में सुधार और संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कार्यबल (टास्क फोर्स) के गठन" का प्रस्ताव किया गया था।

जहाँ हम महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण, उच्च मातृ मृत्यु दर, कुपोषण के उच्च स्तर और लड़कियों की खराब शैक्षिक प्राप्ति को संबोधित करने की आवश्यकता का समर्थन करते हैं, वहीं हम इस बात से असहमत हैं कि इनमें से कोई भी लक्ष्य लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाने से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कदम वयस्कता की सार्वभौमिक आयु के साथ असंगत है, जो कि भारत में सामान्य और विशेष कानून के तहत 18 वर्ष है, जिसमें पीसीएमए, 2006, धर्म आधारित पारिवारिक कानून और भारत द्वारा विधिवत अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है, जैसे कि संसाधनविहीन समुदायों की युवा महिलाओं को आवाज़हीन बनाना, उन्हें हिरासत और अपराधीकरण के प्रति संवेदनशील बनाना, तथा स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से और अधिक दूर करने का खतरा।

भाग ए: बाल/ जल्द विवाह में कमी, जो मुख्य रूप से भारत में हाशिए पर स्थित और संसाधनहीन समुदायों में प्रचलित है

1. राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह में कमी आई है:

एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, 20-24 वर्ष आयु समूह की सभी महिलाओं में से 23% महिलाओं की शादी वर्तमान कानूनी आयु 18 वर्ष से पहले हुई थी, जो एनएफएचएस-4 (2015-16) में दर्ज 26.8% से कम है, और एनएफएचएस-3 (2005-06) में इसी आयु समूह में 18 वर्ष से पहले विवाह करने वाली 47.4% महिलाओं से काफी कम है। लड़कियों के लिए पहली शादी की औसत आयु 2005-06 में 17.2 वर्ष से

बढ़कर 2015-16 में 19 वर्ष और 2019-21 में 19.2 वर्ष हो गई है। प्रवृत्ति से पता चलता है कि बाल विवाह में कमी आई है, और इसकी जगह देर से किशोरावस्था में विवाह को बढ़ावा मिला है, जिसे अधिक सटीक रूप से 'जल्दी अथवा जल्द विवाह' के रूप में वर्णित किया जाता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) में आंकड़ों का राज्यवार पृथक्करण दर्शाता है कि उच्च प्रचलन वाले राज्यों में लगभग दो-पांचवां हिस्सा महिलाएं विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु तक पहुंचने से पहले शादी कर लेती हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल (42%), बिहार (40%), और त्रिपुरा (39%) शामिल हैं; इसकी तुलना में कम प्रचलन वाले राज्य हैं लक्षद्वीप (4%); जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (प्रत्येक 6%); हिमाचल प्रदेश, गोवा, और नागालैंड (प्रत्येक 7%); और केरल और पुडुचेरी (प्रत्येक 8%)।

एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 48.0% महिलाओं की शादी 20 वर्ष की आयु तक हो गई थी और 25-29 वर्ष की आयु के बीच 63.4% महिलाओं की शादी 21 वर्ष की आयु तक हो गई थी।³ इस आंकड़े के आधार पर, प्रस्तावित विधेयक का प्रभाव भारत में होने वाले अधिकांश विवाहों का अपराधिकारण होगा।

2. बाल विवाह तथा जल्द विवाह की घटनाएं हाशिए पर पड़े, गरीब और (बड़े पैमाने पर) ग्रामीण समुदायों में होती हैं, जो गरीबी, अशक्तता और खराब शिक्षा के कारण होते हैं:

सांख्यिकीय और गुणात्मक अध्ययन, दोनों ही भारत में जल्द विवाह के कई प्रमुख कारणों को स्थापित करते हैं, जिनमें गरीबी, सामाजिक हाशिए पर होना, सुरक्षा की कमी, उचित रोजगार के अवसरों की कमी, मानवीय संकट और संघर्ष, साथ ही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में लिंग असमानता शामिल हैं। घर और समुदाय के स्तर पर गरीबी अक्सर सीमित उपलब्धता/पहुँच और खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, खराब बुनियादी ढांचे, और कम अवसरों के साथ जुड़ी होती है। साथ ही, पारंपरिक पितृसत्तात्मक प्रथाओं का मतलब है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर असुरक्षा और डर पैदा होता है, और लड़कियों की यौन पवित्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिससे परिवार की इज्जत के लिए बेटियों का कौमार्य महत्वपूर्ण हो जाता है; गरीबी और सामाजिक हाशिए पर होने की स्थिति में ये प्रथाएँ और भी विकृत हो जाती हैं। न्यूनतम विवाह आयु बढ़ाने जैसा प्रतीकात्मक उपाय लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य और अन्य परिणामों में सुधार करने की बुनियादी बाधाओं को हल नहीं कर सकता। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी के कारण बाल विवाह की संभावना अधिक है, अगर लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच मिलती है तो इसमें कमी आने की संभावना है।⁴ इसलिए

³ भारत रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण 2015-2021 [एनएफएचएस-4], पृष्ठ 165

⁴ गोली, श्रीनिवास, 'बाल विवाह उन्मूलन: प्रगति और संभावनाएँ', नई दिल्ली: चाइल्ड राइट्स फोकस और एक्शन एड, 2016; शिरीन जे. जेजीबाँय, 'भारत में बाल विवाह समाप्ति: प्रेरक और रणनीतियाँ' (अक्षरा सेंटर फॉर इकिटी एंड वेल बीइंग और यूनिसेफ, 2019)

शिक्षा और कम उम्र में विवाह के बीच संबंध है। यह सुझाव देना कि विवाह की आयु बढ़ाने से महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाएगा, पितृसत्तात्मक संस्कृतियों में महिलाओं और लड़कियों की वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से अनदेखा करता है, जिसमें लिंग भूमिकाएं गहराई से समाहित हैं। विधेयक का यह मानना ग़लत है कि जिन परिवारों के पास संसाधन, सस्ती माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या वैकल्पिक आजीविका के अवसर नहीं हैं, या जिनके पास अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा भी नहीं है, उनके पास अपनी वास्तविकताओं से हट कर ऐसा विकल्प चुनने की क्षमता होगी।

3. कम उम्र में शादी लड़कियों के स्कूल छोड़ने का परिणाम है, कारण नहीं।

साक्ष्य दर्शाते हैं कि युवा लड़कियों को शिक्षित करने और सशक्त बनाने में निवेश करना कम उम्र में और जबरन विवाह की समस्या का एक शक्तिशाली निवारक है। जबकि प्राथमिक और जल्द विवाह स्तरों पर लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर गिरावट उत्तेजक है - शुद्ध नामांकन अनुपात 91.58 (प्राथमिक) से सीधा 31.42 (उच्चतर माध्यमिक) तक गिर जाता है।⁵ लड़कियों की शिक्षा में प्रतीत होने वाले लाभ के बावजूद, एनएचएस-4 (2015-16) के अनुसार 15-19 वर्ष की आयु की 49% लड़कियों और 56% लड़कों ने केवल कक्षा 10+ पूरी की थी। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की ड्रॉप-आउट दर में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है: यह 2014-15 में 17.79% से बढ़कर 2016-17 में 19.18% हो गया।⁶

डेटा से पता चलता है कि जल्द विवाह शिक्षा के बाद लड़कियों के बीच पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण कम उम्र में शादी होना नहीं है। NHFS-4 (2015-16) के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों ने अपनी शिक्षा छोड़ने के निम्नलिखित कारण बताए: 24.8% ने पढ़ाई में रुचि की कमी बताई; 19.3% ने शिक्षा की उच्च लागत की सूचना दी; 14.5% ने अवैतनिक घरेलू काम के बोझ को जिम्मेदार ठहराया; केवल 7.9% ने विवाह को स्कूल छोड़ने का कारण बताया। बाल विवाह लड़कियों के स्कूल छोड़ने का कारण नहीं बल्कि इसका परिणाम है।

<https://www.unicef.org/india/media/2556/file/Drivers-strategies-for-ending-child-marriage.pdf>; भारत में बाल विवाह पर सांख्यिकीय विश्लेषण: जनगणना 2011 पर आधारित: (यंग लाइव्स और एनसीपीसीआर - 2017)

https://younglives-india.org/sites/www.younglives-india.org/files/2018-05/Child%20Marriage%20Report%20Final_1.pdf; भारत में प्रारंभिक और बाल विवाह: एक परिदृश्य विश्लेषण (निरंतर ट्रस्ट 2015)

<http://feministlawarchives.pldindia.org/wp-content/uploads/Nirantar-ECM-Report.pdf?>; मैरी ई. जॉन, 'बाल विवाह एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में: भारत से एक नारीवादी विश्लेषण', न्यू यॉर्क, लंदन और नई दिल्ली: राउटलेज, 2021

⁵ राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) 2018। अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के लिए यह आंकड़ा 15% और कम हो जाता है।

⁶ वही। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए ड्रॉप-आउट दर और बढ़ जाती है। लगभग 68.21% एसटी और 62.57% एससी बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुँचने तक स्कूल छोड़ देते हैं और 88.17% एसटी बच्चे और 83.62% एससी बच्चे माध्यमिक स्तर तक पहुँचने तक स्कूल छोड़ देते हैं (पंडिता, 2015)

शिक्षा छोड़ने के लिए 'पढ़ाई में रुचि की कमी' को ज़िम्मेदार ठहराना तीन महत्वपूर्ण कारकों से संबंधित है - कम सीखने का स्तर⁷, प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री की कमी और खराब शिक्षण और अध्ययन की पद्धतियाँ, और भेदभाव⁸ कई छोटे अध्ययनों ने पाया है कि लड़कियों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के डर से कई लोग अपनी बेटियों को माध्यमिक विद्यालय भेजने से कतराते हैं, जो लड़कियों को स्कूल से बाहर निकालने का अतिरिक्त कारण है।⁹ व्यवस्थात्मक जाति और लिंग आधारित भेदभाव भी स्कूल छोड़ने का एक कारण है।¹⁰ अवैतनिक घरेलू काम का बोझ निस्संदेह लड़कियों पर है, और यह लड़कियों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित करता है। जब परिवार शिक्षा को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी से बाहर निकलने के संभावित मार्ग के रूप में नहीं देखते हैं, तो वे उन्हें स्कूलों से निकाल देते हैं। सबसे आसान विकल्प उनकी शादी कर देना है। लड़कियों के बेहतर शैक्षिक परिणामों के लिए इन जटिल कारकों को पहचाना जाना चाहिए।¹¹

विवाह की आयु बढ़ाने के बजाय समग्र शैक्षिक पहुँच, प्रतिधारण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार - ये उपाय सुनिश्चित करेंगे कि लड़कियाँ प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करें। इसके अलावा, चूंकि शिक्षा का अधिकार (RTE) 14 वर्ष से आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए गरीब परिवारों की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुँचना मुश्किल लगता है, जिसमें परिवहन, किताबें और वर्दी से संबंधित लागत शामिल होती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार विवाह की कम आयु और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों की अनुपस्थिति का ठोस सहसम्बन्ध है।¹² इसलिए, माध्यमिक विद्यालयों को आसानी से उपलब्ध कराने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वहनीय बनाने के उपायों के अलावा RTE को 18 वर्ष तक बढ़ाने से स्कूलों में लड़कियों के बने रहने को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

4. कुपोषण, एनीमिया, खराब मातृ/शिशु स्वास्थ्य परिणाम गरीबी, अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण होते हैं, न कि 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह के कारण।

18 वर्ष के बाद विवाह की आयु का माँ और उसके बच्चे के पोषण स्तर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जबकि गरीबी निवारण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे कारक महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और

⁷ प्रथम द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एसईआर) बार-बार कम सीखने के स्तर की ओर इशारा करती है। एसईआर 2018 रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित है।

⁸ सुधारों के बावजूद, पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक पूर्वाग्रह कायम हैं चूंकि समस्या जटिल है, इसलिए विद्वानों ने चेतावनी दी है कि रूढ़िवादिता या ऊपर से नीचे तक संदेश (जैसे कि सामाजिक बुराई के रूप में कम उम्र में शादी) को हटाकर केवल 'स्वच्छता' प्रभावी नहीं है। इसके बजाय सामग्री को लड़कियों के अनुभव के बहुआयामी अभावों को स्वीकार करने की आवश्यकता है (भोग डी. एट अल, 2010; एनसीईआरटी, 2006)।

⁹ लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि समुदायों को लड़कियों की कम उम्र में शादी करने के लिए प्रेरित करती है। (संत्या केजी एट अल, 2019)

¹⁰ नंबिसन, जी., 2010; रामचंद्रन, वी. और नाओरेम, टी, 2013

¹¹ 2001 और 2011 के बीच बाल विवाह दरों में गिरावट को महिला शिक्षा में सुधार, गरीबी में कमी और औसत घरेलू आकार के कारण समझाया गया है। (जेवियर एजेएफ. एट अल, 2019)

¹² कल्पना कन्नबीरन एट अल विवाह में महिलाओं की कम उम्र के कारणों की जांच: तेलंगाना और आंध्र का मामला, ईपीडब्ल्यू 52 (18) 2017; एमवी फाउंडेशन और वे कभी भी खुशी से नहीं रहे... न्याय की लड़ाई जारी है: तेलंगाना में विवाहित लड़कियों की आवाज़, 2018

पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने में कहीं अधिक सहायक होते हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत 53.1 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया, एनीमिया से पीड़ित किशोर लड़कियों (15-19 वर्ष की आयु) का प्रतिशत 54.1 प्रतिशत से बढ़कर 59.1 प्रतिशत हो गया और एनीमिया से पीड़ित पुरुषों की संख्या भी 22.7 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई। विवाह की अधिक आयु माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों से संबंधित है क्योंकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की महिलाएँ ही अधिक आयु में विवाह करती हैं, और ऐसी महिलाएँ अधिक स्वस्थ भी होती हैं और उनकी उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्राप्त होती है। महिलाओं में एनीमिया उनकी विवाह की आयु से प्रभावित नहीं होता है। दूसरे, बौनापन और कमज़ोरी किसी भी अन्य कारक की तुलना में गरीबी से कहीं ज़्यादा मज़बूती से जुड़ी हुई है।

खराब मातृ स्वास्थ्य परिणाम और बाल मृत्यु दर हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। जबकि पारंपरिक साहित्य ने कम उम्र में मातृत्व और उम्र को खराब गर्भावस्था और जन्म परिणामों से जोड़ा है,¹³ पिछले दशक के अध्ययनों ने युवा लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों को इसका कारण बताया है। इस बात के सबूत हैं कि कम उम्र (18 से कम) में गर्भधारण खराब गर्भावस्था परिणामों से जुड़ा हुआ है और 18+ की उम्र गर्भावस्था के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ उम्र है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 18 साल या उसके बाद गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाले खराब स्वास्थ्य परिणाम घरेलू गरीबी, खराब पोषण की स्थिति, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच से उत्पन्न होते हैं, उम्र नहीं।¹⁴

एनएफएचएस-4 डेटा (2015-16) से पता चलता है कि गरीब परिवारों की लड़कियों और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले होने की संभावना अधिक है।¹⁵ इन लड़कियों के वयस्क होने पर भी बच्चे के जन्म के लिए गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना है, चाहे शादी की उम्र कुछ भी हो।¹⁶ गर्भावस्था के दौरान अंतरंग साथी की हिंसा भी खराब मातृ और जन्म परिणामों से जुड़ी हुई है।¹⁷

भारत में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसी ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ी आबादियों में बच्चों का मृत्यु दर अधिक है। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, घरेलू संपत्ति, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ऐसे प्रमुख कारक हैं जो बच्चों, विशेष रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए जीवित और स्वस्थ रहने की संभावना को निर्धारित करते हैं।¹⁸ ये निष्कर्ष उच्च मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के

¹³ संख्या, केजी. एट अल, 2010; गोधा, डी. एट अल, 2013; राज, ए. एट अल, 2010; पॉल, पी., 2018

¹⁴ बनर्जी, बी. एट अल, 2009; मासूमी, एस.जेड. एट अल, 2017 15

¹⁵ एनएफएचएस - 4, 2015-16

¹⁶ मेहरा, एस., और अग्रवाल, डी., 2004

¹⁷ धर, डी. एट अल, 2018; विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), 2013

¹⁸ यह पाया गया कि एससी (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 56 मौतें), एसटी (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 57 मौतें) और ओबीसी (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 51 मौतें) के लिए पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर उन लोगों की तुलना में काफी अधिक है जो एससी, एसटी या

मुद्दों से निपटने के लिए गहरी संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करने के महत्व पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए, स्वास्थ्य परिणामों को संबोधित करने के लिए, केवल शादी की उम्र में देरी करने के हस्तक्षेप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. शिक्षित महिलाओं की बेरोजगारी का कारण शादी की उम्र नहीं बल्कि अच्छे वेतन वाली नौकरी का अभाव है

संशोधन में तर्क दिया गया है कि अगर लड़कियां 21 साल की उम्र के बाद शादी करती हैं तो वह अपनी शादी से पहले ज़्यादा काम के अवसर पा सकेंगी और इसके परिणामस्वरूप उन्हें ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। हालाँकि, हाल के दशकों में महिलाओं के रोज़गार में गिरावट आई है, वही दशक जिनमें कम उम्र में शादी में भी गिरावट देखी गई है। दूसरे, ज़्यादातर महिलाएँ मजबूरी में ऐसी नौकरियों में काम कर रही हैं, जिनका वेतन कम है, और जो अनौपचारिक, आकस्मिक और आम तौर पर खराब कामकाजी परिस्थितियों से ग्रसित हैं। भारत दुनिया के सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर वाले देशों में से एक है। लड़कियों के लिए श्रम बल में प्रवेश करने के अवसर सीमित हैं, "स्वीकार्य" नौकरियों का दायरा छोटा है, और कौशल तक पहुँच सीमित है। कृषि श्रम के अलावा, ग्रामीण लड़कियाँ गाँव में केवल शिक्षक, AWW/ASHA या यहाँ तक कि घर में सिलाई और इसी तरह की नौकरियाँ करना चाहती हैं, जिनमें पुरुषों के साथ बातचीत शामिल नहीं होती (ब्यूटी पार्लर, ANM आदि), और जिन्हें उनके परिवारों और समुदायों द्वारा सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। इसलिए समस्या विवाह की उम्र नहीं, बल्कि अच्छी नौकरियों की कमी, और समाज में महिलाओं के लिए स्वीकार्य काम के बारे में लैंगिक दृष्टिकोण है।

भाग बी: विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से होने वाले अनपेक्षित नुकसान

1. वयस्क होने के बाद युवा महिलाओं के नागरिक अधिकारों को सीमित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

भारत और दुनिया भर में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। प्रस्तावित विधेयक भारत में मौजूदा कानूनी ढांचे के बिल्कुल विपरीत है, जो मतदान, संपत्ति खरीदने और बेचने, अनुबंध करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने आदि जैसे उद्देश्यों के लिए वयस्क होने की कानूनी आयु "18" को मान्यता देता है। भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वयस्क होने की आयु अठारह वर्ष निर्धारित

ओबीसी (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 39 मौतें) से नहीं हैं। घरेलू संपत्ति बढ़ने के साथ पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी गिरावट आती है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर निम्नतम धन पंचम में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 72 मृत्यु से घटकर उच्चतम धन पंचम में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 23 मृत्यु हो गई (एनएफएचएस-4)।

करता है।¹⁹ सभी प्रमुख नागरिक और राजनीतिक अधिकार 18 वर्ष की आयु में प्रभावी होते हैं, जिस आयु में सभी व्यक्ति अपनी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन से संबंधित सभी मामलों में निर्णय ले सकते हैं। विवाह करने और वयस्कों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करने जैसे महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार की गारंटी में देरी करने से 18-21 वर्ष की आयु के बीच की वयस्क महिलाओं के अधिकारों का पूरा आनंद प्रभावित होता है, विशेष रूप से उनके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार।

कुछ संदर्भों और परिस्थितियों में किशोर नाबालिगों की कानूनी क्षमता को भी स्वीकार किया जाता है। बाल श्रम निषेध 14/15 वर्ष से कम उम्र के 'बच्चे' को बचाता है²⁰, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत 14 से 18 साल के बीच के बच्चों को काम करने की अनुमति देता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 "जघन्य अपराध" के आरोपी 16 से 18 वर्ष के बच्चों को वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने और दंडित करने की अनुमति देता है। वयस्कता अधिनियम, 1875 18 वर्ष को वयस्कता की कानूनी उम्र मानता है, धार्मिक कानूनों द्वारा शासित विवाह और परिवार से संबंधित चिंताओं को छोड़कर, जहां कम उम्र में विवाह, रद्दीकरण और तलाक की अनुमति है। बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) संयुक्त आम सिफारिश 31/ आम टिप्पणी 18 (2019) मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार परिषद के संकल्प²¹ बाल विवाह को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि विवाह में कम से कम एक पक्ष 18 वर्ष से कम आयु का हो।

अदालतों ने भी कई मामलों में माना है कि वयस्कों को स्पष्ट रूप से संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार है कि वे जिसके साथ चाहें रह सकते हैं और अपने संबंधों की रूपरेखा तय कर सकते हैं, जिसमें विवाह और सहमति से यौन क्रियाकलाप शामिल हैं। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति में निहित स्वतंत्रता और स्वायत्तता को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है, जो कि अपने साथी को चुनने की क्षमता तक विस्तारित है, जो गोपनीयता और व्यक्तित्व के अधिकार के एक अलंघनीय पहलू का हिस्सा है (के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार)²²। शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम.²³ (2018) 16 एससीसी 368 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस²⁴ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

¹⁹ धारा 3, भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875

²⁰ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

²¹ ए/एचआरसी/आरईएस/41/8

²² (2017) 10 एससीसी 1)

²³ (2018) 16 एससीसी 368

²⁴ (2018) 2 एससीसी 197

“यह कहने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करना अपना महत्व रखता है। वह अपनी पसंद बनाने का हकदार है। जब तक पसंद बनी रहती है, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया की भूमिका नहीं निभा सकते।”

पुट्टास्वामी में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा “[आनुपातिकता] मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक आवश्यक पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असंगत नहीं है।”²⁵

2. विवाह की न्यूनतम आयु को अनिवार्य या ‘आदर्श’ विवाह आयु नहीं समझना चाहिए

कानून में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष होने को अक्सर लैंगिक असमानता के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा का परिणाम मानते हुए, जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, भारतीय विधि आयोग ने पीसीएमए और अन्य संबद्ध कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट संख्या 205 में सिफारिश की कि “लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि इसे अलग क्यों होना चाहिए।”

विवाह की न्यूनतम आयु समाज के लिए आधारभूत अनुपालन को दर्शाती है, जिसे पूरा न करने पर दंड और अभियोजन हो सकता है। यह न तो विवाह की अनिवार्य आयु है, न ही इसे विवाह की आदर्श आयु के साथ भ्रमित किया जाना चाहिए, जिसे कानून निर्धारित या बढ़ावा नहीं दे सकता है। विवाह की न्यूनतम आयु ही वह सीमा है जिसे कानून निर्धारित कर सकता है, यह उस समय को चिह्नित करती है जब विवाह पर राज्य या तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, या इसके विपरीत, जब इसे राज्य या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है। इस विधेयक में इस अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे यह अस्थिर हो गया है। कानून के माध्यम से विवाह के प्रयोजनों के लिए महिलाओं को 21 वर्ष तक शिशु के रूप में मानना पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है।

यह विधेयक समानता और स्वतंत्रता पर समृद्ध न्यायशास्त्र की अनदेखी करता है और गलत तरीके से विवाह की आदर्श आयु को विवाह की न्यूनतम आयु के साथ मिला देता है और वयस्क महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता के उनके मौलिक अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करता है। विवाह में देरी करने के लिए कानून पर अत्यधिक जोर देने से जमीनी स्तर पर व्याप्त असमानता और भेदभाव, साथ ही सामाजिक-आर्थिक अभाव और लड़कियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की कमी को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

²⁵ के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1) पैरा 310 पर

3. बाल विवाह के अभियोगों में चुनिंदा रूप से उन जोड़ों द्वारा स्वयं तय किए गए विवाहों को लक्षित किया जाता है जो माता-पिता की स्वीकृति के विरुद्ध विवाह करते हैं:

साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि आपराधिक कानून का उपयोग उन लड़कियों के विरुद्ध दंडात्मक रूप से किया जाता है जो माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करती हैं, न कि लड़कियों को तय या जबरन विवाह से बचाने के लिए। वर्ष 2008-17 के केस लॉ के विश्लेषण से पता चलता है कि माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्रवाई, आपराधिक अभियोजन और विवाह निरस्तीकरण के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो अक्सर जबरन विवाह, घरेलू दुर्व्यवहार और घर के काम से बचने के लिए माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भाग जाती हैं या विवाह कर लेती हैं, तथा संबंध का पता चलने पर

माता-पिता के क्रोध से बचती हैं।²⁶ निष्कर्षों से पता चलता है कि पीसीएमए कानून का इस्तेमाल भागकर शादी करने या स्व-व्यवस्थित विवाह के विरुद्ध अरेज मैरिज के विरुद्ध दोगुना किया जाता है, तथा पीसीएमए के अंतर्गत बड़ी संख्या में अभियोजन स्व-प्रवर्तित विवाहों से संबंधित हैं।²⁷ कानून का इस्तेमाल जबरन और अरेज मैरिज से सुरक्षा प्राप्त करने या उन्हें चुनौती देने के लिए बहुत कम किया जाता है।²⁸

जबकि आपराधिक अपराधों का इस्तेमाल ज्यादातर भागकर शादी करने के विरुद्ध किया जाता है, पीसीएमए के गैर-दंडात्मक प्रावधानों का इस्तेमाल अरेज मैरिज के मामलों में किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में विवाह के इरादे से अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अभियोजन की तुलना में पीसीएमए के तहत अभियोजन में अंतर परिलक्षित होता है।²⁹ आपराधिक दबाव और बल प्रयोग से जुड़े मामलों के एक अंश को छोड़ दें, तो अभियोजन में चौंका देने वाली असमानता अभी भी नियमित पीसीएमए मामलों की तुलना में भागने को लक्षित करने की ओर इशारा करती है।

²⁶ मेहरा एम, माहेश्वरी एस, भारत में बाल विवाह अभियोजन (पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, 2021); यह भी देखें, मेहरा एम, नंदी ए, लड़कियां शादी करने के लिए क्यों भागती हैं: भारत में किशोरावस्था की वास्तविकताएं और सामाजिक-कानूनी प्रतिक्रियाएं (पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, 2019)।

²⁷ पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, भारत में बाल विवाह अभियोजन - अभिनेताओं, उद्देश्यों और परिणामों का केस लॉ विश्लेषण 2008-2017 (2021)https://www.academia.edu/50087712/Child_Marriage_Prosecutions_in_India_Case_Law_Analysis_of_Actors_Motives_and_Outcomes_2008_2017 पर उपलब्ध है एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बाल विवाह में रुझान: असम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत निर्णयों से अंतर्दृष्टि (2024), 19, https://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2024/08/Report2-ChildMarriage_web.pdf पर उपलब्ध है

²⁸ 366. महिला का अपहरण, अपहरण या उसे विवाह के लिए मजबूर करना, आदि - जो कोई भी किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष तक बढ़ सकता है, और साथ ही वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा; 1[और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूर करने की किसी अन्य विधि के माध्यम से, किसी भी महिला को किसी भी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि वह, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, पूर्वोक्त रूप से दंडनीय होगा]।

आगामी वर्षों में दर्ज मामलों की संख्या	2018	2019	2020
बाल विवाह निषेध अधिनियम	501	523	785
आईपीसी की धारा 366: महिलाओं का अपहरण और भगा ले जाना	3335	3206	2474
उसे शादी के लिए मजबूर करो	4	6	5

ऐसे अभियोगों के परिणामस्वरूप, लड़कियों को अक्सर आश्रय गृहों में रखा जाता है (माता-पिता के पास लौटने से इनकार करने पर, या माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार करने पर), और लड़कों को जेलों या सुधार गृहों में भेज दिया जाता है, जो दुखद रूप से शिक्षा, आजीविका या सशक्तिकरण के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। व्यवहार में, कानून लड़कियों पर माता-पिता और समुदाय के नियंत्रण को लागू करने के लिए आया है, वही चीज़ जिसे कानून को बदलना चाहिए। विवाह की आयु में वृद्धि से वह अवधि बढ़ जाएगी जिसके भीतर धारा 366 आईपीसी के तहत अभियोग चलाए जा सकते हैं, और महिलाओं की हानि, शक्तिहीनता और अधिकारिता का हनन बढ़ जाएगा। कम उम्र में विवाह की संख्या पर प्रभाव, सबसे गरीब आबादी समूहों के युवाओं के लिए विनाशकारी परिणाम हैं, लड़कियों के लिए विवाह की आयु में वृद्धि के साथ ही यह और भी बढ़ जाएगा।

4. यौन प्रजनन स्वास्थ्य सूचना और सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होगी:

विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि से लड़कियों और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी है। महिला कामुकता के इर्द-गिर्द पहले से ही कलंक और सामाजिक वर्जनाएँ लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए यौन प्रजनन स्वास्थ्य सूचना और सेवाओं तक पहुँच को बहुत चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। पुरुष साथियों के अपराधीकरण के अलावा, लड़कियाँ गर्भपात सहित गोपनीय और सुरक्षित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं, क्योंकि POCSO की धारा 19 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहमति के मामलों को पुलिस को 'दुर्व्यवहार' के रूप में रिपोर्ट करना आवश्यक है। विवाह की आयु में देरी करने का कोई भी कदम महिलाओं, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर आबादी की महिलाओं के खिलाफ़ निगरानी, कलंक और दंडात्मक उपायों का विस्तार करेगा, जिससे कई महिलाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो जाएँगी। इसके अतिरिक्त, यह 18-21 वर्ष की आयु वर्ग की वयस्क लेकिन कम उम्र की महिलाओं के लिए विवाह से

पहले यौन संबंध, विवाह के लिए कलंक, भय और आपराधिक मुकदमा चलाने को आकर्षित करेगा और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, गर्भनिरोधक और गर्भपात को और भी कठिन बना देगा।

5. कम उम्र में विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए कानून में संशोधन करने वाले अधिकार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए हानिकारक परिणाम बढ़ेंगे

कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहाँ कम उम्र में विवाह को शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाता है, लड़कियों की न्यूनतम विवाह सीमा बढ़ाने के हानिकारक परिणाम बढ़ेंगे। संशोधनों के माध्यम से, 2017 में कर्नाटक और 2020 में हरियाणा में बाल विवाह को शुरू से ही अमान्य माना जाता है (केंद्रीय कानून के अनुसार वैध होने के बजाय लेकिन अमान्य करने योग्य)। विवाह की आयु बढ़ाने से इन दोनों राज्यों में 21 वर्ष तक विवाहित लड़कियों के सामाजिक वैवाहिक अधिकार खतरे में पड़ जाएँगे, जिससे उनकी स्थिति वास्तविक पत्नियों की हो जाएगी, जबकि अगर वे पति को छोड़कर दोबारा विवाह करती हैं तो उन्हें उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम विवाहित लड़कियों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति को नुकसान पहुँचाएँगे।

जबकि 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच विवाह करने वाली लड़कियों के मामले POCSSO के अंतर्गत नहीं आएँगे, लेकिन चयनात्मक अपराधीकरण के मौजूदा साक्ष्य इस आयु वर्ग के बीच विवाहित और/या सहमति से विवाह करने वाले जोड़ों पर IPC की धारा 366 के विस्तारित उपयोग की ओर इशारा करते हैं। भारी सबूतों के मद्देनजर युवा वयस्कों द्वारा स्वयं तय की गई शादियों का चयनात्मक और लक्षित अपराधीकरण निश्चित है। इसी तरह, अगर विवाह की आयु बढ़ा दी जाती है, तो कम उम्र की माताओं और उनके परिवारों को सामाजिक कल्याण और विवाह से जुड़े लाभों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। न्यायशास्त्र विवाह या 'लिव-इन' रिलेशनशिप में युवा महिलाओं की पसंद के अधिकार को दृढ़ता से बनाए रखता है,²⁹ एक संवैधानिक अधिकार जिसे यह विधेयक बाधित करता है, जो सबसे अधिक संभावना है कि गोपनीयता, स्वायत्तता और पसंद के मान्यता प्राप्त अधिकारों को खत्म करने के लिए सतर्कतावाद, नैतिक पुलिसिंग और प्रेरित अभियोजन को प्रोत्साहित करेगा।

²⁹ लता सिंह [(2006) 5 एससीसी 475; रिट याचिका (सीआरएल) 208/2004]; शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम., (2018) 16 एससीसी 368; शायरा खातून @ शायरा खातून और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (रिट-सी संख्या-19795/2021) इलाहाबाद हाईकोर्ट; पुष्पा देवी बनाम पंजाब राज्य (सीआरडब्ल्यूपी-6314-2021) पी एंड एच हाईकोर्ट; माफ़ी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सीआरडब्ल्यूपी संख्या 691/2021) पी एंड एच हाईकोर्ट

भाग सी: अंतिम सिफारिशें

संक्षेप में, विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से न केवल संवैधानिक, सामान्य और व्यक्तिगत कानूनों, भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों के साथ असंगतता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं; बल्कि यह इस बात पर भी विचार करने में विफल रहता है कि गरीबी के कारण कम उम्र में विवाह होते हैं और ऐसे कानून युवा महिलाओं और हाशिए पर रहने वाली आबादी को अनजाने में नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बजाय, हम निम्नलिखित की सिफारिश करते हैं:

1. पीसीएमए से संबंधित सिफारिशें

a. लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष बनी रहे और पुरुषों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जाए ताकि इसे सार्वभौमिक मानकों, संवैधानिक कानून और मौजूदा न्यायशास्त्र के बराबर लाया जा सके।

b. कम उम्र में विवाह वैध बना रहे, हालाँकि विवाह करने वाले नाबालिग पक्ष के विकल्प पर इसे रद्द किया जा सकता है।

c. कम उम्र में विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार वयस्क होने के पाँच साल तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट कारणों से सीमा अवधि से परे देरी के लिए न्यायिक माफ़ी का प्रावधान हो।

d. पीसीएमए और अन्य कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, विश्वसनीय और प्रभावी कानूनी निवारण सुनिश्चित करते हैं जो महिलाओं और लड़कियों को पीड़ित और गवाह की सुरक्षा की गारंटी देते हैं।

ई. उन जिलों और गांवों में एकल प्रभार पर सीएमपीओ की नियुक्ति करें जहां कम उम्र में विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, लड़कियों की सहायता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ।

एफ. अपनी शादी को रद्द करने की इच्छुक लड़कियों को कानूनी सहायता और यह सुनिश्चित करना कि राज्य योजनाओं के तहत तलाकशुदा महिलाओं को मिलने वाले लाभ उन्हें भी दिए जाएं।

2. लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से विवाहित या कम उम्र में विवाह की संभावना वाली लड़कियों को सशक्त बनाना

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लड़कियों में आकांक्षाओं को बढ़ावा देने, उनके नेतृत्व का निर्माण करने और उन्हें आवाज़ देने के अवसरों के सृजन में निवेश का कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिस्थितियों और अवसरों में बदलाव, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और बेहतर स्कूली शिक्षा में निवेश न केवल विवाह में देरी करने के लिए जाना जाता है, बल्कि महिलाओं को यह चुनने में भी सक्षम बनाता है कि उन्हें कब, किससे और कब विवाह करना है। निम्नलिखित सिफारिशें उस बदलाव का मार्ग हैं।

i. 14-18 वर्ष के किशोरों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करने के लिए विधायी सुधार।

- ii. साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों का विस्तार एवं सुधार करना, जो उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से नकद हस्तांतरण, कठिनाई वाली लड़कियों के लिए पूरक कोचिंग के माध्यम से।
- iii. सभी बच्चों एवं किशोरों के लिए आयु के अनुरूप व्यापक यौन शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- iv. बुनियादी ढांचे, स्वच्छ शौचालयों, लड़कियों की गतिशीलता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले परिवहन में सुधार के लिए निवेश करना एवं प्राथमिकता देना।
- v. महिलाओं एवं लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम, वितरण एवं पहुंच को गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाना चाहिए।
- vi. विश्वसनीय एवं प्रभावी हेल्पलाइन; घरेलू हिंसा से बचने के लिए लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान; लड़कियों एवं अकेली महिलाओं के लिए छात्रावास।
- vii. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सामाजिक एवं कानूनी बाधाओं को दूर करके किशोरों के अनुकूल यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचना एवं सेवाओं तक युवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाती हैं तथा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।

हम स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे हमें समिति के सदस्यों के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण देने की अनुमति दें।

मधु मेहरा (मोबाइल: 9810737686) पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, नई दिल्ली संयोजक, नेशनल कोलिशन एडवोकेटिंग फॉर एडोलसेंट कंसर्न्स (एनसीएएसी) madhu.mehra@pldindia.org

कविता रत्ना (मोबाइल: +91 94489 90480) कंसर्न्स फॉर वर्किंग चिल्ड्रन, बेंगलुरु नेशनल एंकर, यंग वॉयस वर्किंग ग्रुप

kavitaratna@gmail.com

मैरी ई जॉन (मोबाइल: +91 98183 16249) पूर्व प्रोफेसर, सेंटर फॉर वूमन डेवलपमेंट स्टडीज (CWDS), जिन्होंने CWDS और AUD के एक सहयोगी कार्यक्रम के तहत अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (AUD) में पढ़ाया। साथ ही, JNU, नई दिल्ली में वूमन स्टडीज प्रोग्राम की पूर्व उप निदेशक। लेखक: चाइल्ड मैरिज इन एन इंटरनेशनल फ्रेम: ए फेमिनिस्ट एनालिसिस फ्रॉम इंडिया, न्यूयॉर्क, लंदन एंड न्यू दिल्ली: रूटलेज, 2021।

maryejohn1@gmail.com

संगठनों और व्यक्तियों का विवरण इन प्रस्तुतियों को आरंभ करने और समर्थन देने वाले

ए. एनसीएएसी के सदस्यों की सूची

किशोर चिंताओं की वकालत के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीएएसी) के सदस्य:

1.	पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट (पीएलडी) (दिल्ली)	12.	महिला जन अधिकार समिति (एमजेएस) (राजस्थान)
2.	आनंदी (गुजरात)	13.	निरंतर ट्रस्ट (दिल्ली)
3.	एक्शन इंडिया (दिल्ली)	14.	महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडल (मासूम) (महाराष्ट्र)
4.	बटरफ्लाईज (दिल्ली)	15.	प्रेरणा (महाराष्ट्र)
5.	सेंटर फॉर इंक्रायरी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थीम्स (सीईएचएटी) (महाराष्ट्र)	16.	RATI फाउंडेशन (महाराष्ट्र)
6.	काउंसिल टू सुरक्षित न्याय (सीएसजे) (दिल्ली)	17.	सहियार (गुजरात)
7.	विकलांगता अधिकार केंद्र (डीएआरसी) (पश्चिम बंगाल)	18.	निकोल रेंजल (बाल अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता) (दिल्ली)
8.	एनफोल्ड इंडिया (कर्नाटक)	19.	महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए SAMA संसाधन केंद्र (दिल्ली)
9.	HAQ बाल अधिकार केंद्र (दिल्ली)	20.	शक्ति शालिनी (दिल्ली)
10.	हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव (कर्नाटक)	21.	वाई.पी.फाउंडेशन (उत्तर प्रदेश)

बी. यंग वॉयस वर्किंग ग्रुप के सदस्यों की सूची

यंग वॉयस वर्किंग ग्रुप (YVWG) के सदस्य:

1. आइना (ओडिशा)
2. एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स (एएएलआई) (उत्तर प्रदेश)
3. अभिव्यक्ति मीडिया फॉर डेवलपमेंट नासिक (महाराष्ट्र)
4. एक्शन एंड एसोसिएशन (दिल्ली)

5. अग्रिनी (मध्य प्रदेश)
6. अल्फा एजुकेशन सोसाइटी (दिल्ली)
7. अलवर मेवात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (एएमआईडी) (राजस्थान)
8. आंचल (असम)
9. अनहद प्रवाह (मध्य प्रदेश)
10. आरोग्य आगम (तमिलनाडु)
11. एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एक्शन (एपीएसए) (कर्नाटक)
12. एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस (आशा) (झारखंड)
13. पुरस्कार
14. बदलाओ फाउंडेशन (झारखंड)
15. बिहार अंबेडकर स्टूडेंट फोरम (बिहार)
16. बैंगलोर रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (ब्रेड्स) (कर्नाटक)
17. ब्रेकथ्रू ट्रस्ट (दिल्ली)
18. बिहार प्रदेश युवा परिषद (बीपीवाईपी) (बिहार)
19. चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन (सीडीएफ) (महाराष्ट्र)
20. छाया फाउंडेशन (महाराष्ट्र)
21. सेंटर फॉर सोशल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (सीएसईडी) (तमिलनाडु)
22. चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई) (पश्चिम बंगाल)
23. चिल्ड्रन बिलीव (तमिलनाडु)
24. चित्रा डॉन बॉस्को, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)
25. बाल अधिकार ट्रस्ट (सीआरटी) (कर्नाटक)
26. सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (सीवाईएसडी) (ओडिशा)
27. दीक्षा फाउंडेशन (दिल्ली)
28. डॉन बॉस्को मक्कलालय, मैसूर (कर्नाटक)
29. डॉन बॉस्को यादगीर (कर्नाटक)
30. डॉन बॉस्को, देवदुर्गा (कर्नाटक)
31. बॉस्को बैंगलोर (कर्नाटक)
32. डीबीसीएलएम दावणगेरे- (डॉन बॉस्को बाल श्रम मिशन) (कर्नाटक)

33. डॉन बॉस्को होस्पेट (कर्नाटक)
34. डॉन बॉस्को बीदर (कर्नाटक)
35. डॉन बॉस्को प्यार कलबुर्गी (कर्नाटक)
36. डॉन बॉस्को युवाकरा ग्राम, रामानगर (कर्नाटक)
37. फाईंडिंग फाउंडेशन
38. फोफिड फाउंडेशन
39. फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर (राजस्थान)
40. गर्ल्स नॉट ब्राइड्स
41. गुड फाउंडेशन 89. विकल्प संस्थान (राजस्थान)
42. महिलाओं के लिए ग्राम्य संसाधन केंद्र (तेलंगाना)
43. हिमांशु गुप्ता, बाल अधिकार रक्षक
44. महिलाओं पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआरडब्ल्यू) (दिल्ली)
45. आईजीएस, तेजस्विनी परियोजना (झारखंड)
46. एकीकृत ग्रामीण सामुदायिक विकास सोसाइटी (आईआरसीडीएस) (तमिलनाडु)
47. जागो फाउंडेशन (झारखंड)
48. जन सरोकार (हरियाणा) -
49. मल्टी आर्ट एसोसिएशन/एमएए फाउंडेशन (एमएए) (गुजरात)
50. महिला जन अधिकार समिति (एमजेएस) (राजस्थान)
51. महिला मुक्ति संस्थान (एमएमएस) (झारखंड)
52. ममता संस्था (उत्तराखंड)
53. मिलन फाउंडेशन (हरियाणा)
54. नेशनल अलायंस ऑफ विमेन ऑर्गनाइजेशन ओडिशा (एनएडब्ल्यूओ) (ओडिशा)
55. नवचार संस्थान (राजस्थान)
56. निरंतर ट्रस्ट (दिल्ली)
57. परिवार विकास (बिहार)
58. पतंग (ओडिशा)
59. पीपल फॉर चेंज (झारखंड)
60. पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट (पीएडी) (असम)

61. प्रगति जुवक संघ (पीजेएस) (महाराष्ट्र)
62. प्रवाह (दिल्ली)
63. प्रवाह जयपुर इनिशिएटिव (राजस्थान)
64. राजसमंद जन विकास संस्थान (राजस्थान)
65. रेस्टलेस डेवलपमेंट (दिल्ली)
66. रूबरू (तेलंगाना)
67. रूरल पीपल अवेयरनेस एंड यूथ एक्शन भारत में (रुपयानी) (झारखंड)
68. सद्भावना ट्रस्ट (दिल्ली)
69. साकार (उत्तराखंड)
70. साथी (उत्तर प्रदेश)
71. सहयोगिनी (झारखंड)
72. शक्ति - विद्याल (तमिलनाडु)
73. सेवा भारती (ओडिशा)
74. शबनम अजीज (बाल अधिकार कार्यकर्ता)
75. शैशव (गुजरात)
76. शिव शिक्षा समिति रानोली (एसएसएसआर) (राजस्थान)
77. सिंदुआरटोला ग्रामोदय विकास विद्यालय (एसजीवीवी) (झारखंड)
78. श्रमजीवी महिला समिति (एसएमएस) (झारखंड)
79. श्री नृसिंह देव आंचलिका युवा पेरिसडा (एसएनडीएवाईपी) (ओडिशा)
80. युवा सेवा केंद्र (वाईएससी) (दिल्ली)
81. लोगों की शिक्षा और विकास के लिए (स्पीच) (आंध्र प्रदेश)
82. सृजन फाउंडेशन (झारखंड)
83. सिनर्जी संस्थान (मध्य प्रदेश)
84. द कंसर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (सीडब्ल्यूसी) (कर्नाटक)
85. वाईपी फाउंडेशन (उत्तर प्रदेश)
86. द हंगर प्रोजेक्ट (टीएचपी) (दिल्ली)
87. उत्तरी राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्क यूनिशन लिमिटेड (यूआरएमयूएल) (राजस्थान)
88. विकल्प संस्थान (बिहार)

90. विकास सदन (ओडिशा)
91. विराज
92. विशाखा (राजस्थान)
93. ये एक सोच फाउंडेशन (उत्तर प्रदेश)
94. यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (वाईसीडीए) (ओडिशा)
95. यूथ की आवाज (दिल्ली)

**सी. नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों द्वारा समर्थन
नाम पेशेवर विवरण या संगठन संबद्धता**

1. विद्या रेड्डी तुलिर - सीपीएचसीएसए- तमिलनाडु
2. शिरीन जीजीभॉय निदेशक, अक्ष सेंटर फॉर इक्विटी एंड वेलबीइंग - महाराष्ट्र
3. दुनू रॉय हैज़र्ड्स सेंटर - दिल्ली
4. संध्या गौतम निदेशक कार्यक्रम-स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय केंद्र और समन्वयक, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार गठबंधन (एनएएमएचएचआर) - दिल्ली
5. दिव्या मुकंद - दिल्ली
6. पारुल शेठ कार्यकारी निदेशक- गुजरात
7. स्नेहा मिश्रा सचिव, आइना -
8. शिप्रा झा बाल अधिकार कार्यकर्ता - दिल्ली
9. सतीश निदेशक - कर्नाटक
10. निशिता खजाने वकालत और नीति प्रभाव, द कंसर्न्ड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन - कर्नाटक
11. शांता सिन्हा पूर्व अध्यक्ष, एनसीपीसीआर - तेलंगाना
12. हिमांशु गुप्ता पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता - पंजाब
13. जिम जेसुदाँस कार्यकारी निदेशक - तमिलनाडु
14. आर. वेंकट रेड्डी राष्ट्रीय संयोजक - तेलंगाना
15. योगेश वैष्णव विकास निदेशक - राजस्थान
16. पूनम कथूरिया, निदेशक - गुजरात
17. अमिता पित्रे प्रमुख विशेषज्ञ, लिंग न्याय - महाराष्ट्र

18. आरती गोर बाल अधिकार कार्यकर्ता - महाराष्ट्र
19. मीना जैन पूर्व अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी -II -
20. रूबिन मैथ्यू एसडीबी कार्यकारी निदेशक, बैंगलोर ग्रामीण शैक्षिक और विकास सोसायटी (ब्रेड)- कर्नाटक
21. पी.लक्ष पथी कार्यकारी निदेशक एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एक्शन [एपीएसए] - कर्नाटक
22. अरुणा जोशी निदेशक-कार्यकारी सचिव - गुजरात
23. खुशबू जैन रिसर्च स्कॉलर, एफएयू, एर्लागिन-नूरेमबर्ग, जर्मनी - हरियाणा
24. रोशनी नुगेहल्ली यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन (युवा) - महाराष्ट्र
25. रीता चौकसी, सुनंदा, रेशमा, कमल, सेजल, री ना, विभूति, कृति सामाजिक कार्यकर्ता - गुजरात
26. अनुश्री जयरथ कार्यक्रम समन्वयक - लैंगिक न्याय - दिल्ली
27. वेदा भारद्वाज द हंगर प्रोजेक्ट - दिल्ली
28. मयूरी धूमल परियोजना प्रभारी - महाराष्ट्र
29. दीप्ति कोलाको सलाहकार- अनुसंधान एवं सूचना प्रबंधन, द कंसर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन - कर्नाटक
30. सौम्या माहेश्वरी सहायक। प्रोफेसर, लॉ, मुंजाल यूनिवर्सिटी - हरियाणा
31. अमृता दास गुप्ता एसोसिएट डायरेक्टर - पश्चिम बंगाल
32. आसिफ इकबाल महासचिव - दिल्ली
33. अनुराधा राजन कार्यकारी निदेशक - महाराष्ट्र
34. मंजुला प्रदीप राष्ट्रीय संयोजक - गुजरात
35. डॉ किरण मोदी संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी - दिल्ली
36. जीविका शिव वकील सामाजिक कार्यकर्ता - दिल्ली
37. तन्वी झा राज्य समन्वयक - झारखंड
38. अंकुरम सुमित्रा संस्थापक सचिव - तेलंगाना
39. वनिता एन मुखर्जी एक्टिविस्ट - दिल्ली
40. रेनू खन्ना सह संस्थापक, कॉमन हेल्थ - गुजरात
41. सिंधु नाइक - 42. मनीष आचार्य निदेशक गुजरात
43. ऋचा हमसफर - उत्तर प्रदेश
44. रवि वर्मा आईसीआरडब्ल्यू - दिल्ली
45. मालिनी घोष एक्टिविस्ट/शोधकर्ता - दिल्ली
46. अजय कुमार सचिव - झारखंड

47. काजल जैन -
48. रंजना कान्हारे -
49. शुभदा देशमुख -
50. तृप्ति मालती - -
51. मीना सचिव - उत्तर प्रदेश
52. डालिया रॉय निदेशक - पश्चिम बंगाल
53. प्रियंका दास पर्यवेक्षक, कार्यक्रम महिला एवं बालिका अधिकार - पश्चिम बंगाल
54. ऋतंभरा मेहता स्वतंत्र सलाहकार - लिंग, कामुकता, पॉश, डीईआई - दिल्ली
55. हमीदा खातून सद्भावना ट्रस्ट - उत्तर प्रदेश
56. छोटक ग्यात्सो - लद्दाख 57. रेनु मिश्रा कार्यकारी निदेशक, आली - उत्तर प्रदेश
58. इशानी भट्टाचार्य कार्यक्रम अधिकारी, बालिका शिक्षा कार्यक्रम - दिल्ली
59. करुणा फिलिप कार्यक्रम समन्वयक, बाल शिक्षा का अधिकार और संरक्षण - राजस्थान
60. डॉ. वासुदेव शर्मा एनवी कार्यकारी निदेशक, कर्नाटक 61. सतीश जीसी राज्य संयोजक - कर्नाटक
62. शकुंतला पामेचा निदेशक - राजस्थान
63. सुनीता धर - दिल्ली
64. गीता रामसेशन एडवोकेट, -मद्रास उच्च न्यायालय - तमिलनाडु
65. अपर्णा चंद्रा एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु - कर्नाटक
66. महेंद्र कुमार - -
67. बैताली गांगुली कार्यकारी निदेशक- जबला एक्शन रिसर्च ऑर्गनाइजेशन - पश्चिम बंगाल
68. जशोधरा दासगुप्ता स्वतंत्र शोधकर्ता - उत्तराखंड
69. प्रज्ञा जोशी स्वतंत्र शोधकर्ता - राजस्थान
70. राजेश भट्ट संयोजक, सीआरसीजी। - गुजरात
71. नंदिता गांधी अक्षरा - महाराष्ट्र
72. गीता.एम परियोजना सचिव - कर्नाटक
73. कावेरी परियोजना प्रबंधक - कर्नाटक
74. जगदीश अभियान समन्वयक, ईके साथ, सीएचएसजे - दिल्ली
75. स्मृति एमएचआरसी समन्वय समिति - मध्य प्रदेश